भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 364

बुधवार, दिनांक 24 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा का वार्षिक उत्पादन</u>

364. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:
श्री अरविंद गणपत सावंत: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है और यह कुल विद्युत खपत की कितने प्रतिशत मांग को पूरा करता है;

(ख) क्या भारत विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो देश में विद्युत की कितनी कमी है और इसे किस प्रकार पूरा किया जा रहा है;

(घ) क्या राज्य सरकारों को आपूर्ति की जा रही विद्युत उनकी मांग के अनुरूप है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य उपयोगी कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी)

(क) विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष 2024-25 (मई, 2024 तक) के लिए कुल विद्युत उत्पादन की अपनी प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ देश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) स्रोतों से वार्षिक विद्युत उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार हैः

वर्ष	अक्षय ऊर्जा विद्युत उत्पादन (बीयू में)	कुल उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की प्रतिशत हिस्सेदारी
2021-22	330.03	22.12%
2022-23	372.39	22.92%
2023-24	364.60	20.96%
2024-25 (मई, 2024 तक)	61.84	19.19%

(स्रोतः सीईए)

(ख) से (घ): अप्रैल से जून, 2024 के महीनों के दौरान देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति अनुलग्नक में दी गई है।

(ङ) सरकार ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है, जिनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

- सरकार ने सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया है और दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सब-ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को मजबूत किया है। इसके अलावा, सौभाग्य योजना के तहत सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण किया गया।
- साथ ही, सरकार किसी भी छूटे हुए घरों के विद्युतीकरण के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) की वर्तमान योजना के तहत राज्यों की सहायता कर रही है।
- छोटे ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत संयंत्रों, स्टैंड अलोन सौर विद्युत चालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए फायदेमंद है, बल्कि ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग को भी पूरा करती है।
- 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सौर लगाने के लिए दिनांक 13.02.2024 को पीएम-सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई।

अनुलग्नक

'नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा का वार्षिक उत्पादन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 24.07.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 364 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अप्रैल-जून, 2024 की अवधि के दौरान विद्युत आपूर्ति की स्थिति (अनंतिम)		
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ऊर्जा आवश्यकता (एमयू में)	आपूर्ति की गई ऊर्जा (एमयू में)
अंडमान और निकोबार	114	112
आन्ध्र प्रदेश	20,501	20,501
अरुणाचल प्रदेश	245	245
असम	3,314	3,309
बिहार	12,601	12,514
चंडीगढ़	578	578
छत्तीसगढ़	11,106	11,104
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2,696	2,696
दिल्ली	11,614	11,606
डीवीसी	6,762	6,761
गोवा	1,437	1,431
गुजरात	42,404	42,404
हरियाणा	19,332	19,321
हिमाचल प्रदेश	3,252	3,237
जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख	4,815	4,791
झारखंड	4,140	4,089
कर्नाटक	23,704	23,704
केरल	8,529	8,527
लक्षद्वीप	18	18
मध्य प्रदेश	25,240	25,217
महाराष्ट्र	53,338	53,334
मणिपुर	264	264
मेघालय	491	491
मिजोरम	166	166
नागालैंड	233	233
ओडिशा	11,996	11,991
पुडुचेरी	970	970
पंजाब	20,515	20,515
राजस्थान	28,946	28,744
सिक्किम	137	137
तमिलनाडु	35,385	35,385
तेलंगाना	19,411	19,411
त्रिपुरा	494	494
उत्तर प्रदेश	48,846	48,765
उत्तराखंड	4,682	4,668
पश्चिम बंगाल	20,806	20,775
संपूर्ण भारत	4,51,746	4,51,172

(स्रोतः सीईए)

*****